

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा वभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-1165
उत्तर देने की तारीख-08/12/2025

वदेश में उच्च शिक्षा

+1165. श्री स सकांत से थल:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

- (क) उच्च शिक्षा के लिए वर्ष 2024 में वदेश जाने वाले भारतीय छात्रों की संख्या कतनी है और 2023 के आंकड़ों से इसकी तुलना कस प्रकार की जाती है;
- (ख) उक्त छात्रों द्वारा चुने गए प्रमुख गंतव्य देश कौन-कौन से हैं और इनके वषय कौन-कौन से हैं;
- (ग) सरकार द्वारा छात्रों के वदेश जाने के लिए चहिनित कए गए कारक क्या हैं;
- (घ) वदेशी अहर्ताओं को मान्यता प्रदान करने और ऐसे छात्रों की भारत वापसी को सुगम बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ठठाने का वचार है; और
- (ङ.) वदेशों में भारतीय छात्रों के सामने आने वाली चुनौतियों, जैसे वीजा संबंधी बाधाओं, बढ़ती जीवन-यापन लागत और भू-राजनीतिक जो खमों को कम करने के लिए क्या उपाय कए गए हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): आपवासन ब्यूरो (बीओआई) द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2023 और वर्ष 2024 में वदेश जाते समय अपनी यात्रा का उद्देश्य अध्ययन/शिक्षा बताने वाले भारतीयों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	2023	2024

उच्चतर शिक्षा हेतु वदेश जाने वाले भारतीयों के द्वारा संबंधित आप्रवासन निकासी प्रदान करने के समय प्रस्तुत उद्देश्य को बीओआई द्वारा मैनुअल रूप से उनके मौखिक प्रकटीकरण अथवा गंतव्य देश के वीजा के प्रकार के आधार पर दर्ज कर लिया जाता है। इस आंकड़े के आधार पर, शीर्ष गंतव्य देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी शामिल हैं। तथापि, इन आंकड़ों में वदेशों में वद्यार्थियों द्वारा किए जा रहे पाठ्यचर्यों के प्रकार शामिल नहीं हैं।

वदेशों में उच्चतर शिक्षा व्यापक अवसरों, कैरियर की बेहतर संभावनाओं और सार्थक अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन की आकांक्षाओं द्वारा निर्देशित व्यक्तिगत इच्छा और पसंद का क्षेत्र है। सरकार ने वीजा अनुमोदन, शिक्षणक मान्यता और अन्य देशों के साथ वद्यार्थियों के आवागमन की सुविधा के लिए योग्यता की पारस्परिक मान्यता (एमआरक्यू) और प्रवासन और गतिशीलता साझेदारी समझौते (एमएमपीए) संबंधी करार जैसे रूपरेखा तंत्र के माध्यम से विभिन्न उपाय किए हैं।

भारत में वदेशी डिग्री की मान्यता की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने "वदेशी शिक्षा संस्थानों से प्राप्त अहर्ताओं को मान्यता और समतुल्यता प्रदान करने संबंधी विनियम, 2025" को अधिसूचित किया है। विनियम <https://equivalence.ugc.ac.in/uploads/regulation.pdf> पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, यूजीसी ने वदेशी अहर्ताओं को समतुल्यता प्रदान करने के लिए पोर्टल <https://equivalence.ugc.ac.in/> का संचालन किया है।

वदेशों में अध्ययन करने वाले भारतीय वद्यार्थियों सहित भारतीय नागरिकों को साधन-परीक्षण के आधार पर स्थल पर सुविधा प्रदान और उनके द्वारा किए गए आकस्मिक व्यय को पूरा करने करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा वदेशों में सभी भारतीय मशनों और पदों में भारतीय सामुदायिक कल्याण कोष (आईसीडब्ल्यूएफ) की स्थापना की गई है। वदेशों में भारतीय मशनों/पद उच्चतर शिक्षा के लिए वदेश की यात्रा करने वाले भारतीय वद्यार्थियों को उनके साथ और साथ ही मदद पोर्टल पर पंजीकृत करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं ताकि उनकी शिकायतों और मुद्दों का मामलों तरीके से समाधान किया जा सके।
